(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Allotment of lands to various Institutions in Delhi

1823. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have finalised guidelines for allotment of land in Delhi to Educational institutions, Hospitals, Nursing Homes etc.; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b). Yes, Sir. The allotment of land by DDA to Educational institutions and Hospitals is made under the provision of Rule 20 of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981. The sites for Nursing Homes are disposed of by auction.

The land belongs to L&DO is allotted to educational institutions, Hospitals, Nursing Homes etc., on the basis of the examination of each case according to policy guidelines of Government.

Setting up of new stel plant

1824. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any new major steel plants in the country during the Eighth Five Year Plan period; and

(b) if so ,the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV) : (a) and (b). There are proposals to set up two new major steel plants in the country, one at Vijayanagar in Karnataka and another at Daitari in Orissa. However, it has not been possible to take up implementation of these projects because of resource constraints. The availability of resources during the Eighth Five Year Plan period will be known only after it is finalised.

Modernisation of integrated Steel plants of Steel Authority of India Limited

1825. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for the modernisation of integrated steel plants of Steel Authority of India; and

(b) if so, the details thereof and the total amount including foreign exchange likely to be incurred thereon ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b). Yes, Sir. While the projects for the modernisation and technological upgradation of Durgapur Steel Plant and Rourkela Steel Plant are already under implementation with sanctioned cost estimates of Rs. 2667.6 crores (inclusive of Rs. 685 Cr. of foreign exchange) and Rs. 2461 crores (inclusive of Rs. 396 Cr. of foreign exchange) respectively, Government are currently considering two more proposals of Steel Authority of India Ltd. (SAIL) for modernisation of its steel plants, details of which are as follows :—

(i) Bokaro Steel Plant : A proposal based on the Detailed Project report prepared by the Soviets, to instal Continuous Casting facilities and revamping of hot strip mill with increase in plant capacity to 4.5 million tonnes of crude steel at Bokaro at an estimated cost of Rs. 1352.36 crores (inclusive of Rs. 632.50 crores of foreign exchange) to be implemented in a period of 36 months from the placement of orders is being considered for an investment decision.

(ii) HSCO : After examining various options a proposal of SAIL to modernise Bumper Words of HSCO and produce 1.75 million tonnes of saleable steel at an esti-

mated cost of Rs. 6520 crores (inclusive of Rs. 1565 crores of foreign exchange) in 5 years time is also being considered for an investment decision.

गंगा-जल के बंटवारे के मुद्दे को लेकर भारत और बंगलादेश के मध्य विवाद

1826. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा-जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर भारत और बंगलादेश के मध्य विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे को लेकर हुये विवाद को समाप्त करने के लिये अभी तक कोई वार्ताएं हुई हैं;

(ग) इन वार्ताओं के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या हाल ही में बंग्लादेश के विदेश मंत्री के वार्ता हेतु भारत आने के समय इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी ; और

(ङ) यह मुद्दा कब तक सुलझा लिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस समय तक गंगा जल के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है। सचिवों की समिति की अप्रैल, 1991 में हुई बैठक में यह सहमति हुई थी कि ऐसे बंटवारे के लिये कोई उपयुक्त आधार परिकल्पित करने के वास्ते एक संयुक्त तकनीकी दल संगत भू स्थिति का पता करने के लिये बांटे जाने वाले गंगा प्रवाहों पर आधारित भारत और बंग्लादेश के क्षेत्रों का दौरा करेगा।

(घ) और (ङ) जी हां। इन दोनों देशों की सुविधाजनक तारीखों को आगामी बातचीत करने की सहमति हुई है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य

1827. **श्री रणजीत सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1991 को "इंडियन एक्सप्रैस" में "पंजाब गवर्नमेंट सस्पेंड वर्क आन एस0वाई0ई0एल0 केनाल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने सतलुज-यमुना लिंक नहर-निर्माण परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं के कार्य में लगा दिया है ;

(ग) यदि हां, तो सतलुज-यमुना लिंक नहर-निर्माण में कार्यरत कितने कर्मचारियों को अन्यत्र भेज दिया गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस परियोजना के मुख्य अभियन्ता का पद अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है, यदि हां, तो कब से ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार के अनुसार, सतलुज-यमुना संपर्क नहर निर्माण परियोजना की नामावलियों पर इस समय लगभग 2000 कुशल और अकुशल कार्य प्रभारित कर्मचारी कार्यरत हैं और अधिशेष हुये कर्मचारियों में से अब तक 850 अकुशल कर्मचारियों को अन्य कार्य पर लगा दिया गया है।

(घ) इस परियोजना के मुख्य इंजीनियर का पद 23-7-1990 से रिक्त पड़ा हुआ है।